रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 2004/माघ 17, 1925
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2004/MAGHA 17, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2004

सा.का.नि. 104(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं; नामतः-

1. लघु शीर्षक और प्रारम्भ-

(i) इस नियमावली को भारतीय आर्थिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाएगा ।

(ii) यह संशोधन 6 सितम्बर, 2000 से प्रभावी माना जाएगा ।

2. भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 की सूची-1 के लिए निम्नलिखित सूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी; नामतः-

"सूची-I

भारतीय आर्थिक सेवा के पदों के लिए तैनाती का विवरण

क्रम संख्या	मंत्रालय अथवा विभाग	उच्च प्रशासनिक ग्रेड पर पदों की संख्या (वरिष्ठ सलाहकार अथवा सलाहकार) (22400-525-24500 रू0)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पर पदों की संख्या (सलाहकार) (18400-500-22400 रू0)	ग्रेड-I पर पदों की संख्या (संयुक्त निदेशक अथवा उपायुक्त अथवा उप सलाहकार अथवा निदेशक) 12000-325-16500रू.)	ग्रेडIII. पदों की संख्या (उप-निदेशक अथवा सहायक सलाहकार अथवा सहायक आयुक्त) (10000-325-15200 रू.)	ग्रेड-IV पर पदों की संख्या (सहायक निदेशक अथवा अनुसंधान अधिकारी) (8000-275-13500रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	वित्त मंत्रालय					
(क)	आर्थिक कार्य विभाग		3	16	12	4

(ख)	व्यय विभाग			2		
(ग)	राजस्व विभाग	1				
(घ)	कंपनी कार्य विभाग		1	2	2	2
(ङ)	एकाधिकार प्रतिबंधी व्यापार आयोग			1		
(2)	**कृषि मंत्रालय**					
(क)	कृषि और सहकारिता विभाग		1	4	3	
(ख)	आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय	1	6	14	12	6
(ग)	कृषि लागत और मूल्य आयोग		1	4	4	4
(घ)	पशु पालन और डेरी विभाग			1		
(3)	**ग्रामीण विकास मंत्रालय**		1	6	5	2
(4)	**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**					
(क)	उपभोक्ता मामले विभाग	1		1	4	
(ख)	वायदा बाजार आयोग			2	5	5
(5)	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय**				1	
(6)	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**					
(7)	**गृह मंत्रालय**		1	1	3	2
	आसूचना ब्यूरो					
(8)	**शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन मंत्रालय**			2		
(क)	शहरी विकास तथा गरीबी उन्मूलन विभाग					
(ख)	नगर और ग्राम योजना संगठन		1			
(ग)	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन			1	2	
(9)	**श्रम मंत्रालय**			1	1	2
(क)	विभाग सम्पूर्ण					
(ख)	श्रम ब्यूरो	1		3	7	5
(10)	**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय**		1	4	6	5
(क)	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग					
(ख)	आर्थिक सलाहकार का कार्यालय			1	1	1
(ग)	शुल्क आयोग		2	2	4	4
(घ)	वाणिज्य विभाग		1	7	4	3
(ङ)	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय		1	3	3	3
(च)	विदेशी व्यापार महानिदेशालय			4	5	
(11)	**लघु उद्योग मंत्रालय**				4	
(क)	मंत्रालय संपूर्ण					
(ख)	लघु उद्योग विकास आयुक्त का कार्यालय			1		
(12)	**जल संसाधन मंत्रालय**		2	1	14	15
(क)	मंत्रालय संपूर्ण					
(ख)	केन्द्रीय जल आयोग		1		1	
(13)	**योजना आयोग**			2	2	2
(क)	आयोग संपूर्ण					
(ख)	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	1	4	50	27	23

(14)	**संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**			11	26	7
(क)	दूरसंचार विभाग					
(15)	**विद्युत मंत्रालय**	1		1		
(क)	विभाग संपूर्ण					
(ख)	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण			1		
16.	**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय**		1	2		
17.	**सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय**					
	मंत्रालय संपूर्ण			1	3	2
18.	**कपड़ा मंत्रालय**					
(क)	विभाग		1	1		1
(ख)	जूट आयुक्त का कार्यालय, कलकत्ता				1	1
(ग)	कपड़ा आयुक्त का कार्यालय, मुम्बई				1	
(घ)	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय				1	1
19.	**रेल मंत्रालय**	1				
20.	**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**					
(क)	शिक्षा विभाग		1			
	महिला तथा बाल विकास विभाग		1			
21.	**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**					
	स्वास्थ्य विभाग		1			
22.	**इस्पात मंत्रालय**		1			
23.	**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय**					
(क)	रसायन तथा पेट्रोरसायन विभाग		1			
(ख)	उवर्रक विभाग		1			
(ग)	राष्ट्रीय भेषज मूल्य निर्धारण प्राधिकरण			1		
24.	**पर्यावरण और वन मंत्रालय**		1			
25.	**नागर विमानन मंत्रालय**		1			
26.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग**			1		
	गोवा और दमन दीव सरकार का सांख्यिकी, योजना तथा मूल्यांकन निदेशालय			1	1	
	कुल योग	7	37	158	166	100

टिप्पणियां :

(1) योजना आयोग में क्रम संख्या 13(क) पर ग्रेड-I पर पदों की संख्या (50) है जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड पर उन्नयन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 4 पद शामिल हैं। इसी के अनुसार पदों का उन्नयन कर लिया गया है, परन्तु वे अभी तक उच्च स्तर पर प्रचालित नहीं किये गए ;

(2) भारतीय आर्थिक सेवा में मौजूदा ग्रेड-I तथा ग्रेड-II को एक एकल ग्रेड में विलय कर दिया गया तथा केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ग्रेड-I के रूप में पदनामित किया गया। इसी प्रकार, भारतीय आर्थिक सेवा में 14,300-400-18,300 रूपए के वेतनमान में एक गैर कार्यरत चयन ग्रेड को भी शुरू किया गया है ;

(3) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के कुलपदों में से वरिष्ठ कार्य पदों अर्थात् वरिष्ठ समयमान और ऊपर के पद का 30 प्रतिशत गैर कार्यरत चयन ग्रेड में (14,300-400-18,300 रूपए) होगा, जिन पदों पर अपर सलाहकार/निदेशक/अपर आयुक्त/संयुक्त सलाहकार होंगे;

(4) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्ति संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अधिसूचित की जाएंगी जो संबंधित मंत्रालय/विभाग में संगठनात्मक संरचना और कार्य की प्रवृत्ति पर निर्भर होगी। कुछ मंत्रालयों में, अधोलिखित अर्थव्यवस्था अथवा सांख्यिकीय, सलाहकार पदों के साथ पूर्वयोजित किए जा सकते हैं, यह संगठन में कार्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है।''

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय आर्थिक सेवा का गठन 1.11.61 को किया गया था तथा भारतीय आर्थिक सेवा नियमावली, 1961 को उसी दिन अधिसूचित किया गया। उक्त नियमावली के नियम-5, उप-नियम (2) में इन नियमों के उपबंधों के अनुसार वित्त मंत्रालय की सहमति से समय-समय पर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली सेवा की प्राधिकृत क्षमता के लिए प्रावधान है। कैडर समीक्षा तथा नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भारतीय आर्थिक सेवा की पुनर्संरचना में तथा तत्पश्चात् सरकार द्वारा 6 सितंबर, 2000 को विभिन्न ग्रेडों में सेवा की प्राधिकृत क्षमता को संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन का प्रस्ताव विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में विभिन्न ग्रेडों में संशोधित स्वीकृत क्षमता तथा उसके वितरण को प्रभावी करने के लिए किया गया है। चूंकि, संशोधित क्षमता दिनांक 6 सितंबर, 2000 को अनुमोदित की गई थी, इसलिए पूर्वप्रभावी संशोधन आवश्यक हो गया है ताकि संशोधित क्षमता को उस तिथि जिस पर सरकार ने अनुमोदन दिया था, से प्रभावी हो सके। तथापि, पूर्व प्रभावी संशोधन सेवा के किसी भी मौजूदा सदस्य को प्रतिकूल प्रभावित नहीं करेगा।

[सं. 11015/1/99-आईईएस (खण्ड-III)]

योगेश चन्द्र, सलाहकार

टिप्पणी:- ये मूल नियम सा.का.नि.सं0 1321 दिनांक 1 नवम्बर, 1961 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे। कई उत्तरावर्ती संशोधन किए गए तथा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए, अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II खण्ड 3 (i) दिनांक 9 अक्तूबर, 2003 में सा.का.नि. 800 (अ) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2004

G.S.R. 104(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following further amendment in the Indian Economic Service Rules, 1961, namely:-

1. Short title and commencement-

(1) These rules may be called the Indian Economic Service (Amendment) Rules, 2004.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 6th day of September, 2000.

2. In the Indian Economic Service Rules, 1961, for Schedule-I the following Schedule shall be substituted, namely: -

"SCHEDULE-I

Statement of Duty Posts for the Indian Economic Service

S.No.	Ministry or Department	Number of posts at Higher Administrative Grade (Senior Adviser or Adviser) (Rs.22400-525-24500)	Number of posts at Senior Administrative Grade (Adviser) (Rs.18400-500-22400)	Number of posts at Grade I (Joint Director or Deputy Commissioner or Deputy Adviser or Director) (Rs. 12000-325-16500)	Number of posts at Grade III (Deputy Director or Assistant Adviser or Assistant Commissioner) (Rs.10000-325-15200)	Number of posts at Grade IV (Assistant Director or Research Officer) (Rs.8000-275-13500)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Ministry of Finance**					
(a)	Department of Economic Affairs		3	16	12	4
(b)	Department of Expenditure			2		
(c)	Department of Revenue	1				
(d)	Department of Company Affairs		1	2	2	2
(e)	Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission			1		
2.	**Ministry of Agriculture**					
(a)	Department of Agriculture and Co-operation		1	4	3	
(b)	Directorate of Economics and Statistics	1	6	14	12	6
(c)	Commission for Agricultural Costs and Prices		1	4	4	4
(d)	Department of Animal Husbandry and Dairying			1		
3.	**Ministry of Rural Development**		1	6	5	2
4.	**Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**					
(a)	Department of Consumer Affairs	1		1	4	
(b)	Forward Markets Commission			2	5	5

426 GI/04-2

5.	**Ministry of Food Processing Industries**				1	
6.	**Ministry of Road Transport and Highways**					
	Department proper		1	1	3	2
7.	**Ministry of Home Affairs**					
	Intelligence Bureau			2		
8.	**Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation**					
(a)	Department of Urban Employment and Poverty Alleviation		1			
(b)	Town and Country Planning Organisation			1	2	
(c)	National Building Organisation			1	1	2
9.	**Ministry of Labour**					
(a)	Department proper	1		3	7	5
(b)	Labour Bureau		1	4	6	5
10.	**Ministry of Commerce and Industry**					
(a)	Department of Industrial Policy and Promotion			1	1	1
(b)	Office of Economic Adviser		2	2	4	4
(c)	Tariff Commission		1	7	4	3
(d)	Department of Commerce		1	3	3	3
(e)	Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics			4	5	
(f)	Directorate General Foreign Trade				4	
11.	**Ministry of Small Scale Industries**					
(a)	Ministry proper			1		
(b)	Office of Development Commissioner for Small Scale Industries		2	1	14	15
12.	**Ministry of Water Resources**					
(a)	Ministry proper		1		1	
(b)	Central Water Commission			2	2	2
13.	**Planning Commission**					
(a)	Commission proper	1	4	50	27	23
(b)	Programme Evaluation Organisation			11	26	7

14.	**Ministry of Communications and Information Technology**					
	Department of Telecommunications	1		1		
15.	**Ministry of Power**					
(a)	Department proper			1		
(b)	Central Electricity Authority			2	1	
16.	**Ministry of Petroleum and Natural Gas**		1	2		
17.	**Ministry of Statistics and Programme Implementation**					
	Ministry proper			1	3	2
18.	**Ministry of Textiles**					
(a)	Department proper		1	1		1
(b)	Office of Jute Commissioner, Calcutta				1	1
(c)	Office of Textile Commissioner, Mumbai				1	
(d)	Office of Development Commissioner for Handicrafts				1	1
19.	**Ministry of Railways**	1				
20.	**Ministry of Human Resource Development**					
(a)	Department of Education		1			
(b)	Department of Women and Child Development		1			
21.	**Ministry of Health and Family Welfare**					
	Department of Health		1			
22.	**Ministry of Steel**		1			
23.	**Ministry of Chemicals and Fertilisers**					
(a)	Department of Chemicals And Petrochemicals		1			
(b)	Department of Fertilisers		1			
(c)	National Pharmaceuticals Pricing Authority			1		
24.	**Ministry of Environment and Forests**		1			
25.	**Ministry of Civil Aviation**		1			
26.	**Department of Development of North Eastern Region**			1		

27.	**Directorate of Statistics, Planning and Evaluation, Government of Goa**			1	1	
	Grand Total	7	37	158	166	100

Notes:

(1) The number of posts (50) at Grade-I in the Planning Commission at Serial No. 13(a) includes 4 posts approved by the Cabinet for upgradation to Senior Administrative Grade. Posts have been upgraded accordingly, but have not yet been operated at the higher level;

(2) Grade-I and Grade-II hitherto existing in the Indian Economic Service were merged into a single grade and designated as Grade-I, as per the recommendation of the Central Pay Commission. Similarly, a Non-Functional Selection Grade in the scale of Rs.14,300-400-18300 was also introduced into the Indian Economic Service;

(3) Of the total posts at the Junior Administrative Grade, 30% of senior duty posts, i.e., posts in Grade-III and above will be in the Non-Functional Selection Grade (Rs.14,300-400-18300), with designations being Additional Adviser or Director or Additional Commissioner or Joint Adviser;

(4) The designation of various posts in individual Ministries or Departments is to be notified by the Ministry or Department concerned depending upon the organisational structure and nature of the work in the respective Ministry or Department. In some Ministries, the subscript economic or statistical may be prefixed with advisory designation depending on the nature of work in the organisation."

Explanatory Memorandum

The Indian Economic Service was constituted on 1.11.61 and the Indian Economic Service Rules, 1961 were also notified on the same date. Rule 5 sub-rule (2) of the said rules provide for the authorised strength of the service to be fixed by the Controlling Authority from time to time with the concurrence of the Ministry of Finance in accordance with the provisions of these rules. In the Cadre Review and restructuring of the IES approved by the Controlling Authority and thereafter, by the Government on the 6th September, 2000, the authorised strength of the service in various grades has been revised. The amendment is proposed to give effect to the revised sanctioned strength in various grades and their distribution over different Ministries/Departments. Since the revised strength was approved on the 6th September, 2000, the retrospective amendment has become necessary to give effect to the revised strength w.e.f. the date it was approved by the Government. The retrospective amendment, however, will not have the effect of adversely affecting any existing members of the Service.

[No. 11015/1/99-IES(Vol. III]

YOGESH CHANDRA, Adviser

Note: The principal rules were published vide G.S.R. No. 1321 dated the 1st November, 1961. Subsequently number of amendments were made and published in the Gazette of India, the last of the amendments were published in the Gazette of India Extra Ordinary Part II, Section 3 (i) dated the 9th October, 2003 vide G.S.R. 800(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.